प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 12 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 20 – 27 मार्च 2017 मूल्य पांच रूपए

कब से होगी धर्मशाला दूसरी राजधानी इसका अधिसूचना में नहीं है कोई जिक्र

शिमला/बलदेव शर्मा

धर्मशाला प्रदेश की दूसरी राजधानी होगी मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के इस ऐलान से ही प्रदेश भर में इस पर एक बहस चालू हो गयी है। क्योंकि वीरभद्र के ऐलान के बाद यह मुद्दा विधानसभा पटल तक जा पहुंचा है। सरकार को इस आश्य की अधिसूचना तक जारी करनी पड़ गयी है। शिमला और मण्डी संसदीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में वीरभद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध भी सामने आने लग पड़ा है। संगठित तरीके से इसके विरोध की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमीरपुर और कांगड़ा के संसदीय क्षेत्रों में भी विधायक संजय रत्न और मन्त्री सुधीर शर्मा ही इस फैसले के मुखर पक्षधर होकर सामने आये हैं। जिन लोगों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है वह इस फैसले पर वीरभद्र की राजनीतिक सूझबूझ पर ही प्रश्न उठाते नजर आ रहे हैं।

इस फैलसे के राजनीतिक आकलन के लिये इसमें जारी हुई अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अधिसूचना राज्यपाल को संविधान में धारा 154(1) प्रदत कार्यकारी शक्तियों के तहत मुख्यसचिव वीसी फारखा के आदेश से जारी हुई हैं। सरकार की सारी अधिसूचनाएं राज्यपाल की इन शक्तियों के तहत ही जारी होती हैं। धर्मशाला को राजधानी बनाना एक ऐसा फैसला है जिसके वित्तिय और प्रशासनिक पक्ष भी हैं बल्कि सरकार के हर फैसले के यह पक्ष रहते ही हैं। इसलिये किसी भी फैसले का मसौदा मन्त्रीमण्डल की स्वीकृत के लिये ले जाने से पहले उस पर वित और विधि विभाग की भी राय ली जाती है। यह राय मन्त्रीमण्डल के समक्ष रखी जाती है। मन्त्रीमण्डल के पास लाये गये प्रारूप में इसका उल्लेख रहता है। लेकिन धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा के बाद जब वीरभद्र पर इसकी विधिवत अधिसूचना जारी करने का दबाव आया तो जो प्रारूप मन्त्रीमण्डल के लिये तैयार किया गया उस पर वित्त और विधि विभाग की राय का कोई उल्लेख ही नहीं है। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक विधि और वित विभाग के पास यह प्रारूप भेजा ही नहीं गया है। मन्त्रीमण्डल के समक्ष रखे गये प्रारूप में केवल यही कहा गया है कि धर्मशाला में 2005 से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर गद्दी, गुज्जर, राजपूत, ब्रहामण आदि कल्याण बोर्डो की बैठकें भी आयोजित हो रही हैं। इसलिये धर्मशाला को दूसरी राजधानी अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। मन्त्रीमण्डल ने भी इसी प्रारूप को

Government of Himachal Pradesh,
General Administration Department
B-Section.

No. GAD-B-(A)-1-1/2017 Dated Shimla-2, the 3rd March, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the executive powers conferred under article 154(1) of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify Dharamshala, Distt. Kangra as Second Capital of the State of Himachal Pradesh.

By Order,

V C Pharka
Chief Secretary to the,
Govt. of Himachal Pradesh.
3rd March, 2017

Endst. No. GAD-B-(A)-1-1/2017 Dated
Copy forwarded for information and necessary action to:-

अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने से प्रदेश के खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? यहां पूरा सचिवालय कब स्थानान्तरित होगा? सचिवालय के साथ संबद्ध निदेशालय कब स्थानान्तरित होंगे? क्या इसके लिये धर्मशाला में अतिरिक्त भवन निमार्ण की आवश्वकता होगी? ऐसे निर्माण के लिये कितनी भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी और यह अधिग्रहण प्रक्रिया कब से शुरू होगी? यहां पर राजधानी कितना समय कब से लेकर कब तक कार्यशील रहेगी। ऐसा कोई उल्लेख इस प्रारूप में नही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक इन पक्षों पर कोई विचार भी शुरू नही हुआ है। इसीलिये जारी हुई अधिसूचना में यह तक नही कहा गया है कि यह अधिसूचना कब से लागू होगी। जो अधिसूचनाएं जारी होने के साथ ही लागू हो जाती है। उनमें ऐसा लिखा जाता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नही है।

जारी हुई अधिसूचना की अस्पष्टता से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार इस फैलसे को लेकर ईमानदारी से गंभीर है या नहीं ? क्योंकि इस अधिसूचना और इस आश्य के मन्त्रीमण्डल के पास लाये गये प्रारूप से यही इगित होता है कि महज मुख्यमन्त्री की घोषणा का मान रखने और लोगों को भ्रम की स्थिति में रखने के लिये ही ऐसी अस्पष्ट अधिसूचना जारी की गयी है। क्योंकि इस अधिसूचना का यह भी अर्थ निकलता है कि धर्मशाला इसी समय से शिमला के बराबर राजधानी बन गयी है और सरकार का सारा प्रशासनिक ढ़ांचा समानान्तर रूप से धर्मशाला में भी कार्यरत है। जबकि

शेष पृष्ठ 2पर.....

जीडीपी का 33.96% हुआ सरकार का कर्जभार

2016–17 में 485.44 करोड़ घटी विद्युत से आय

शिमला/बलदेव शर्मा

सरकार वित्तिय अनुशासन में रहे इसके लिये वित्तिय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत सरकार को जबाव देह बनाया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद सरकार जीडीपी के 3% से अधिक ऋण नही ले सकती हैं। केन्द्र सरकार के वित्त विभाग ने मार्च 2016 में अगला वित्तिय वर्ष शुरू होने से पहले एक पत्र भी राज्य सरकार का लिखा था। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया था वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार 3540 करोड़ से अधिक का ऋण नही ले सकती है। अब दस मार्च को सदन में रखे गये बजट दस्तावेजों में एफआर वीएम नियम 4 और 5 के तहत आयी जानकारी के मुताबिक 2016-17 के संशोधित अनुमानों में चालू वित्तिय वर्ष का कुल कर्ज भार जीडीपी का 33.96% कहा गया है। चालू वित्त वर्ष का जीडीपी 1,24,570 करोड़ रहने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि यह कर्जभार 42303 करोड़ हो गया है। अभी 31 मार्च को वित्तिय वर्ष बन्द होने से पहले इसी महीने में 2400 करोड़ का कर्ज और लिया गया है। लेकिन बजट की व्याख्यात्मक विवरणिका में 31 मार्च 2016 को यह कर्जभार 38567.82 करोड़ दिखाया गया है। निश्चित है कि जब 31 मार्च 2017 के बाद इस वित्तिय वर्ष का वास्तविक अकालन सामने आयेगा तो कर्ज का यह आंकड़ा 45 हजार करोड़ से ऊपर होगा। इस बढ़ते कर्जभार पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि भविष्य में आने वाली सरकार के लिये कर्ज लेना कठिन हो जायेगा।

इस बढ़ते कर्जभार के साथ यदि यह आकलन और विश्लेषण किया जाये की इस इतने बड़े कर्ज का निवेश कहां किया गया है तो ऐसा कुछ भी नजर नही आता है। जिससे की सरकार की आय में नियमित बढ़ौत्तरी होगी। आज तक प्रदेश सरकार हिमाचल को विद्युत राज्य प्रचारित और प्रसारित करती आ रही है। यह दावा किया जाता रहा है कि अकेले विद्युत से ही प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायेगा। इसके लिये कई बार विद्युत नीति में संशोधन भी किये गये हैं। निवेशकों के लिये कई सुविधायें प्रदान की गयी हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद वीरभद्र के इस कार्यकाल में विद्युत में कोई निवेश नही हो पाया है। बल्कि विद्युत क्षेत्र से सरकार की आय लगातर घटती जा रही है। वर्ष 2015-16 में विद्युत से कर और गैर कर राजस्व के रूप में सरकार को 1474.74 करोड़ वार्षिक योजना के तहत कृषि और परिवहन के बाद यह निवेश का तीसरा बड़ा क्षेत्र है। वर्ष 2017- 18 में भी योजना के तहत इसके लिये 680 करोड़ रखे गये है। विद्युत से सरकार की लगातर घटती आये के साथ ही विद्युत परिषद का अपना ऋण भार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा संकेत है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र सरकार के वित्तिय संकट का सबसे बड़ा कारण बन जायेगा।

सरकार का राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व आय के अुनपात में वर्ष 2016-17 जंहा यह घाटा 3. 51% रहने की उम्मीद है वंही वर्ष 2021-22 तक यह चार गुणा से भी बढकर 14.07% तक पहुंच जाने का अनुमान बजट दस्तावेजों में रखा गया है। सरकार की राजस्व आय जहां 26676.70 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 37038.27 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं पर राजस्व व्यय 27613.27 करोड़ से बढ़कर 42252.58 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है इस सारे परिदृष्य में कैपिटल आऊटले जो सीधे विकास कार्यो से संबधित है वह भी लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 2016-17 में यह केवल 3823.68 करोड़ है वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना 5700 करोड़ की है। लेकिन इस वर्ष के लिये कैपिटल आऊटले केवल 3475.36

शेष पृष्ठ 2पर.....

वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आएगी:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हैं और आगे भी रहेंगे तथा सातवीं बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अग्निहोत्री ऊना जिला के चिंतपूर्णी में विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चरूड़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व स्पष्ट है, वहीं भाजपा मुख्यमंत्री के पद पर उम्मीदवार को लेकर विभाजित है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की रैलियों में लोगों का भारी संख्या में शामिल होना वर्तमान सरकार की लोकप्रियता को दर्शाता है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आएगी।

भाजपा नेताओं की इस बयानबाजी कि वर्तमान सरकार ने कोई भी रोजगार नहीं दिया है, की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने चार साल के शासन काल के दौरान 43 हजार से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान 19 हजार रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2000 पटवारियों की नियुक्ति की गई है और पहली बार 3000 सहायक पटवारी भी रखे गए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्य विधानसभा सत्र के दौरान लोगों की मांगों को सदन में रखने के विपरीत वाकआउट करने व नारेबाजी में ही विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों की विकास से सम्बन्धित कोई भी मांग नहीं रखी और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ माफिया राज का दुष्प्रचार आरम्भ किया है। वास्तव में नशे के व्यापार में शामिल एक व्यक्ति की जब जांच की गई, तो पता चला कि वह भाजपा से सम्बन्धित है।

अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पूरी तरह से करमुक्त है और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला है।

अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों की फसल को जंगली जानवरों, बंदरों व आवारा पशुओं से बचाने के लिए आरम्भ की गई है, जिसके तहत खेतों के चारों और बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने के मामले का अनावश्यक रूप से विरोध कर रही है, क्योंकि वे इस दिशा में निर्णय नहीं ले सके, जबकि एक मुख्यमंत्री कांगड़ा से भी सम्बन्धित रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वां नदी के तटीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि केंद्र द्वारा जारी नहीं की गई है, जिसके कारण कार्य अवरूद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व के दौरान ऊना के लिए इंडियन ऑयल का डिपू स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त ऊना के लिए आईआईआईटी स्वीकृत की गई है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, परन्तु प्रदेश भाजपा नेता इसमें भी रोड़ अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा नेताओं के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय का मामला लम्बित पड़ा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने राजनीतिक विरोधियों पर कीचड़ उछालने में विश्वास रखते हैं, जबकि उन्हें स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए।

राज्य में 7.29 लाख घरों में पानी के कनेक्शन:विद्या स्टोक्स

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने नई दिल्ली में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 'सभी के लिए जल' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर सम्बोधित करते हुए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के तहत बीते वर्षों के दौरान निधि में काफी कमी की गई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य के प्रत्येक घर में पेयजल सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अभी तक कुल 13,41,940 घरों में से 7,28,873 घरों में पानी के कनेक्शन प्रदान किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत 15.29 प्रतिशत के मुकाबले 54.31 प्रतिशत है।

स्टोक्स ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जनगणना गांवों को नब्बे के दशक के मध्य सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके उपरांत, बस्तियों में यह सुविधा प्रदान करने पर बल दिया गया। वर्तमान में कुल 53604 बस्तियों में से 33362 बस्तियां पूरी तरह से कवर बस्तियों की श्रेणी में शुमार हैं, जिनमें फरवरी, 2017 तक अधिकतम 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि आंशिक तौर पर कवर शेष 20242 बस्तियों में जहां प्रति व्यक्ति 70 लीटर प्रतिदिन से कम पेयजल प्राप्त हो रहा है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित पेयजल की अधिकतम मात्र प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए, राज्य सरकार ने ब्रिक्स बैंक के साथ एक परियोजना तैयार की है।

राज्य सरकार पानी की गुणवत्ता की निगरानी को उचित महत्व प्रदान कर रही है। पेयजल स्रोतों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य में 42 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें से 14 जिला स्तर पर तथा 28 प्रयोगशालाएं उपमण्डल स्तर पर स्थापित की गई हैं।

8 लाख किसान क्रेडिट कार्डों में से केवल 2.4 लाख ही क्रियाशील

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बैंकिंग प्रणाली आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि सरकार के सामाजिक सुरक्षा तथा विकास सम्बन्धी अभियान प्रभावी ढंग से सफल हो सके। उन्होनें प्रदेश के बैंकों में ऋण जमा करवाने के घटते अनुपात पर चिंता व्यक्त की तथा बैंककर्मियों से विकास क्षेत्रों तथा संगठित निवेश का पता लगाने का आग्रह किया ताकि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

उन्होंने 8 लाख किसान क्रेडिट कार्डों में से केवल 2.4 लाख के ही क्रियाशील होने पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने बैंक कर्मियों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन के माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग तथा लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रदेश में इस योजना को आरम्भ होने से अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत किसानों को 9266 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

उन्होंने बैंक कर्मियों से नकदी पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों तथा लोक उपयोगिता सेवाओं में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनिलस का प्रबन्ध करने का आग्रह किया।

डॉ. बाल्दी ने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र गतिविधियों में 82 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रदेश में दिसम्बर तक वार्षिक क्रेडिट प्लान 2016-17 के अन्तर्गत अब तक 9823 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

उन्होंने बैंक कर्मियों से शिमला के प्रशिक्षण केन्द्रों के पंचायती राज पदाधिकारियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षर प्रदान करने का आग्रह किया ताकि बैंकिंग प्रणाली के लाभ प्रदेश के जमीनी स्तर के लोगों तक पहुंचे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद मेहता ने बैंकों से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो सिंचाई योजनाओं को वित्त पोषित करने का आग्रह किया।

प्रबन्धक निदेशक तथा यूकों बैंक के सीईओ आर.के.टक्कर ने 2005 करोड़ रुपये की कुल अनुपयोगी सम्पत्ति की वृद्धि पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बढ़ते एनपीए के बुरे चलन से बैंकों पर नए ऋण विस्तार में बहुत दबाव पड़ रहा है। बैंकों को कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटान समझौता के साथ-साथ उगाही पर भी बल देना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अमरनाथ ने बैंकों को जमीनी स्तर पर वित्तीय समग्र अभियान को बढ़ावा देने पर बल देने को कहा ताकि बैंकिंग सेवाओं को विस्तृत किया जा सकें।

मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड दीपक कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है तथा बैंक कर्मियों के समन्वय से किसानों की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

कर्मचारी सरकार की रीढ़: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उद्योग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय की निजी सचिवों तथा कार्मिक सहायक संघ द्वारा वरिष्ठ विशेष निजी सचिव अविनाश लॉ तथा कार्मिक सहायक नरेश जरयाल के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कर्मचारी सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में अहम भूमिका अदा करते हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी मेहनतकश, समर्पण तथा प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा गत चार वर्षों में 2455 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने दोनों अधिकारियों के खुशहाल, स्वस्थ तथा संतोषजनक सेवानिवृत जीवन की कामना की।

संघ ने प्रदेश के प्रति लम्बी सेवाएं देने के लिए दोनों अधिकारियों को शॉल, हिमाचली टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय की निजी सचिवों तथा कार्मिक सहायक संघ के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस समारोह के लिए समय निकालने के लिए आभार व्यक्त किया।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on PWD form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Dalhousie Division. HP PWD Dalhousie for the following work from valid registered contractors of appropriate class enlisted with HP PWD so as to reach in his office on or before **20.04.2016 up to 10:30 AM.** And will be opened at **11:00 AM.** On the same day in the presence of intending contractors or their representatives who may like to present . the application fro issue of tender form will be received on **19.04.2016. up to 12:00** Noon in his office against cash payment (Non-refundable)

The Earnest Money in the shape of N.S.C. Time deposit account Post Office account /FDR in any of the Post office Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer HPPWD Division Dalhousie must be accompany with the tender. Conditional tender and tender receives without earnest money summarily be rejected. The XEN reserve the right to reject the tender without assigning any reason. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. If holidays declare suddenly by the Govt.on the above date. The tender shall be received and open on the next working day. The intending contractor/firm will have to produce all documents at the time of making application such as income tax clearance /sale tax clearance /Labour registration and copy of enlistment special care should be given to write the rate both in figures and in words failing which their tender are likely to bee rejected.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Class Tender	Time For Comp.
1.	Restoration of damages due to Laying of OFC on Shahpur Sihunta Chowari road (SH- P/L 25 mm thick Bituminous concrete and V- Shape drain at km 24.0 to 25/0)	2,01,312/-	4,030/-	350/-	Class "D" & C only	01 Month.
2.	Restoration of damages due to Laying of OFC on Shahpur Sihunta Chowari Jot Chamba Bharmour road (SH- P/L 20 mm thick Premix carpet, seal coat and V- Shape drain at km 59/0 to 60/0)	2,37,356/-	4,750 /-	350/-	Class "D" & C only	01 Month.
3.	C/O Rain Shelter on Tandi Dharoon road at RD 4/134 Disst. Chamba (H.P.)	74,343/-	1,490/-	350/-	Class "D"&C only	03 Month.
4.	C/o Dramnallah Dhullara Rajain Khargatta raod Km. 0/0 to 130 (SH:- C/O Rain Shelter on at km 2/825)	74,350/-	1,490/-	350/-	Class "D" &C only	03 Month

TERMS AND CONDITIONS:-
1The earnest money should be deposited first for individual work and then tender documents will bee issued.
2. The undersigned reserve the right to reject/ cancel, any tender without assigning any reason stage.
3. Telegraphically /Fax tender are not acceptable .
4. The tender form will not be issued to those Contactors who have not more than two works at the time of issue of tenders forms In this regard contractor has to submit an affidavit that he is not having more then two work in hand.

Adv. No.- 4948/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

गोवा व मणिपुर में खरीद-फरोख्त से सरकार बनाना लोकतांत्रिक प्रणाली पर धब्बा:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के चुरूडू (अम्ब) में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि जन आकांक्षाओं के विपरीत और जनादेश के विरूद्ध किसी व्यक्ति को नेता चुनना सरासर गलत है। हाल ही में गोवा व मणिपुर में खरीद-फरोख्त से सरकार का गठन करना लोकतांत्रिक प्रणाली पर धब्बा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ राजनेताओं ने ईवीएम में छेड़छाड़ सम्बन्धी शिकायतें की हैं, जिसके तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि

किसी को संदेह बाकी न रहे। हालांकि मुझे अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि यदि ईवीएम को लेकर कोई अनिश्चिता है तो उसे अगले चुनावों से पूर्व जांचना चाहिए।

स्वयं भू नेताओं पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आंतरिक समितियों का गठन चुनाव से होना चाहिए, न कि मनोनयन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि जो कुछ नेता मनोनीत किए गए हैं, उन्हें लोकतांत्रिक नियमों का पालन करना चाहिए तथा अपने आपको सर्वोपरि नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोगों से ऊपर नहीं हैं। नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और मतदान के माध्यम से चुनाव होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की मूल भावना कायम रहे।

मुख्यमंत्री ने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों पर कहा कि 14वें वित्त आयोग ने इन स्थानीय निकायों के अनुदान को रोका है, परन्तु सरकार अपने संसाधनों से इन्हें धनराशि उपलब्ध करवाएगी। जिला परिषद व पंचायत समितियों को मिलने वाली धनराशि पर रोक लगाने पर उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सरकार की बड़ी गलती है और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संशोधन का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाया जायेगा, ताकि जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को धनराशि का रास्ता खुल सके।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में विकास न होने की अफवाहें फैला रहे हैं, परन्तु उन्हें स्वतंत्र तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर विश्वास करना चाहिए, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को समग्र विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में अव्वल आंका है। उन्होंने प्रदेश भाजपा नेताओं को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध सही भाषा प्रयोग करने की भी सलाह देते हुए कहा कि भाजपा नेता मर्यादाओं को भूल गए हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सही नहीं है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी आलोचना का विरोध नहीं किया है, परन्तु केवल सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, जो लोकतंत्र के हित में है।

उन्होंने स्थानीय विधायक एवं राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार की मांग पर महाविद्यालय खोलने, जबलेहड़ व रपोह मिसरा की पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने व लोहारा के चौणीदेवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत करने व स्वां नदी के चुरूडू में पुल के निर्माण करने, अम्ब में स्टेडियम, राजकीय प्राथमिक पाठशाला थाडा को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा माध्यमिक पाठशाला हम्बोली को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नरैण अम्ब में विज्ञान कक्षाएं तथा कथाल में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलमेहरा में विज्ञानप खण्ड, हीरानगर, अम्ब, सतोहड़ भाकरा (हरियाली बस्ती) और कुटेहड़ा खैरलांजी, वार्ड नम्बर 5 में टयूब बैल स्थापित करने की मांगों को स्वीकृति प्रदान की।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने चौकीमनियार में 13.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री महाविद्यालय के भवन, 8 करोड़ रुपये की लागत से टकराला में सब्जी मण्डी, 1.23 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अम्ब की विज्ञान खण्ड, 1.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अम्ब के सलोह-परामब जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से क्षेत्र के छह गांवों की जनता लाभान्वित होगी।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुरूडू के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने गारनी खड्ड पर 6.38 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल तथा 2.25 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (कन्या) के अतिरिक्त भवन का भी लोकार्पण किया।

कुलदीप कुमार ने दलवाड़ी चिंतपूर्णी में महाविद्यालय खोलने, रपोह मिसरा और जबहेड़ पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहारा के चौणीदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्यन करने और कुछ स्कूलों को स्तरोन्नत करने, अम्ब में स्टेडियम का निर्माण के अतिरिक्त स्वां नदी के चुरूडू में पुल के निर्माण की मांग की।

कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री का चौकीमनियार में डिग्री महाविद्यालय के भवन की आधारशिला रखने के अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र के लिए 35 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

गिरी जल आपूर्ति योजना को जल्द बहाल करे आईपीएच विभाग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, विद्युत तथा नगर निगम शिमला के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिमला शहर की जल आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए गिरी जल आपूर्ति योजना को तुरंत प्रभाव से बहाल करने के निर्देश

दिए, ताकि शहर तथा कस्बों के लोगों को प्रतिदिन जलापूर्ति उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि रिसाव की मुरम्मत तथा पानी के टैंकों के ओवर फ्लो को रोकने में नाकाम होने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 41 पंचायतों की लगभग 75 हजार आबादी को जल आपूर्ति के लिए अप्रैल मध्य तक शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 105 करोड़ रुपये की लागत की घोह-घण्डल जल आपूर्ति योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि नगर निगम शिमला की सीमाओं के भीतर कुल 44 एमएलडी पानी की आवश्यकता है तथा नगर निगम शिमला के बाहर कुल 4 एमएलडी पानी की आवश्यकता है। गिरी स्रोत की मुख्य पाइप लाईन की मुरम्मत के पश्चात 5 से 6 एमएलडी पानी की बढ़ोतरी होगी।

प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अनुराधा ठाकुर ने कहा कि गिरी जल आपूर्ति योजना की संपूर्ण राइजिंग को बदला जा रहा है और कार्य लगभग पूरा होने को हैं, जिससे वर्तमान आपूर्ति में 5 से 6 एमएलडी पानी की बढ़ौतरी होगी। अश्वनी खड्ड से पानी की आपूर्ति जनवरी, 2016 से बंद है, जिससे पानी की आपूर्ति में 9 से 10 एमएलडी पानी की कमी आ रही है।

हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनारथा ने कहा कि निश्चित समयावली पर पूरे शहर को एक समान पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, शिमला नगर निगम आयुक्त पंकज राय, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन -चीफ ए. के. बहरी, हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक पी.सी. नेगी भी बैठक में उपस्थित थे।

केन्द्र ने रोकी स्वां तटीकरण की धनराशि-मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। ऊना जिला के गगरेट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जनसभा के अवसर पर अपने सम्बोधन में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्वां नदी के तटीकरण के लिए धनराशि जारी नहीं करने पर केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता सत्ता में वापसी पर प्रदेश के विकास और जन कल्याण के दावे करते हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे स्वां नदी तटीकरण के लिए धनराशि जारी करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाने में नाकाम रहे।

उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा नेता ब्यान जारी कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे विशेष तौर पर गगरेट और हरोली विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देंगे लेकिन उन्होंने भाजपा नेताओं को सावधान किया कि वे जनता की शक्ति को अनदेखा न करें और इन चुनावों में भाजपा पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। उन्हें स्मरण होना चाहिए कि क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि इन क्षेत्रों का विकास कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित बनाया है।

अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता राज्य में ड्रग माफिया की बात करते हैं लेकिन वास्तव में ऐसे लोग भाजपा में शामिल हैं जिसका प्रमाण पड़ौसी राज्य में हाल ही में संपन्न चुनाव हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऊना जिला का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि गगरेट और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में टिकटों को लेकर भी भाजपा विभाजित है और यह समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।

अग्निहोत्री ने प्रश्न किया कि जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री है तो हिमाचल में एम्स स्थापित करने में विलंब क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर भी राजनीति कर रही है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में अकेले सरकार क्षेत्र में ही 43,000 रोजगार प्रदान किए गए हैं तथा 19000 और रोजगार देने का वायदा राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1450 रुपये किया गया है जबकि सामाजिक सुरक्षा पैंशन 650 से बढ़ाकर 700 रुपये की गई है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अपनी जमीन पर टयूबवैल स्थापित करने वालों को 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

एनएच के कार्य का दायित्व केन्द्र सरकार का: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की धर्मसाल मंतान में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए केन्द्रीय परिवहन तथा उच्च मार्ग मंत्री द्वारा घोषित 61 राष्ट्रीय उच्च मार्गो के कार्य को आरम्भ करने तथा डीपीआर तैयार करने में देरी के लिए भाजपा अनावश्यक रूप से ही प्रदेश सरकार को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समझना चाहिए कि अभी तक प्रदेश सरकार को डीपीआर तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि प्रदान नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की घोषणा के उपरांत स्वीकृतियां प्राप्त करने में समय लगता है तथा उपरोक्त कार्य का आंबटन राज्य सरकार ने नहीं बल्कि केन्द्र सरकार ने किया हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के लिए 61 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल के लोगों को सड़क कार्य आरम्भ न होने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जबकि यह कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 117 कॉलेज हैं तथा इनके माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं विशेषकर लड़कियों को उनके घरद्वार के निकट गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो रही है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत धर्मसाल मंतान खास में कालू-दी बड़ स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

क्षेत्र के विधायक तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने क्षेत्र की तीन पंचायतों को लाभान्वित करने वाली पेयजल योजना के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। कुलदीप कुमार ने कहा कि क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, परन्तु राज्य सरकार ने समय-समय पर मांगों पर विचार करते हुए हैंडपम्प स्थापित करने की मांग स्वीकार की है तथा अब 2.50 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से संभवत: ही पानी की समस्या हल होगी। उन्होंने क्षेत्र में हुए अन्य विकास के बारे भी जानकारी दी।।

उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के कुछ स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, माता शीतला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा चिकित्सकों के पद भरने का आग्रह किया।

ग्राम पंचायत धर्मसाल मंतान की प्रधान गुरमीत तथा चिंतपूर्णी खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कैप्टन प्रीतम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा स्थानीय मुद्दों को उठाया।

बुद्धिमान व्यक्ति भी तब घोर परेशानी से घिर जाता है, जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करता है कि सही क्या है और गलत क्या है.....चाणक्य

सम्पादकीय

पांच राज्यों के जनादेश

अभी हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद चार राज्यों में भाजपा और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। इस जनादेश को लेकर जो भी पूर्वानुमान लगाये जा रहे थे वह गलत सिद्ध नहीं हुए हैं। क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो बहुमत भाजपा को मिला है शायद इसकी उम्मीद भाजपा को भी नही रही होगी। यहां सपा और कांग्रेस के गठबन्धन को 50.50% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 22.5% और सपा को 28% जबकि भाजपा को 41%। लेकिन भाजपा 41% वोट लेकर 325 सीटें जीत गयी और सपा कांग्रेस 50.50% वोट लेकर भी 50 के आंकड़े को नहीं छू पायी। उत्तराखण्ड और गोवा में मुख्यमन्त्री तक हार गये। पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की हार ने आप के राजनीतिक विकल्प होने की सारी सभांवनाओं को लम्बे समय तक के लिये अनिश्चिता के गर्व में डाल दिया है। इस परिप्रेक्ष में यह जनादेश देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा दशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह तय है। इसलिये इस जनादेश का विश्लेषण करने के लिये राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर विचार करना आवश्यक होगा।

जो जनादेश आज आया है इसके बीज अन्ना आन्दोलन में बोये गये थे जिनकी पहली फसल लोकसभा चुनाव परिणामों के रूप में सामने और दूसरी अब। अन्ना आन्दोलन का मुख्य बिन्दु था भ्रष्टाचार समाप्त करना और इसके लिये व्यवस्था परिवर्तन को इसका साधन बताया गया। लेकिन जब व्यवस्था परिवर्तन के लिये राजनीतिक मंच के गठन करने की बात उठी तो पूरा अन्ना आन्दोलन विखर गया। आन्दोलन के संचालको और आयोजकों में उभरे मतभदों से खिन्न होकर अन्ना ने ममता के सहारे अलग मंच का जो प्रयास किया वह शक्ल लेने से पहले ही ध्वस्त हो गया। अन्ना की यह असफलता स्वभाविक थी या प्रायोजित यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। लेकिन इस आन्दोलन का बड़ा फल मोदी और भाजपा को मिल गया तथा छोटा फल केजरीवाल को। मोदी और भाजपा के पास संघ परिवार की वैचारिक जमीन थी। केन्द्र में सरकार बनने के बाद इस जमीन की ऊवर्श शक्ति को और बढ़ाने के लिये मोदी के मन्त्रीयों ने अपने भाषणों में अपनी सोच का खूलकर प्रचार जारी रखा। भले ही मोदी ने राजधर्म निभाते हुए अपने मन्त्रीयों को संयम बरतने की सलाह दी। लेकिन इस सलाह का संज्ञान लेने की बजाये यह लोग अपने कर्म में लगे रहे और इस कर्म का परिणाम उत्तर प्रदेश के जनादेश के रूप में सामने है। संघ परिवार की वैचारिक सोच स्पष्ट है वह भारत को हिन्दु राष्ट्र देखना और बनाना चाहते हैं। इसका माध्यम सता होता है और सता उसको मिल गयी है। हिन्दु राष्ट्र की अवाधारणा देश की वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रसांगिकऔर वांच्छित हो सकती है उसके लिये संघ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा को समझना आवश्यक होगा। इस विचारधारा को समझे बिना इस पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह स्वीकार्य है या नही। संघ और भाजपा अपने ऐजैन्डा को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और उसपर उनका काम जारी है क्योंकि उनको यह अवसर देश की जनता ने अपने प्रचण्ड जनादेश के माध्यम से दिया है।

दूसरी ओर कांग्रेस के पास जो वैचारिक धरोहर थी उस पर भ्रष्टाचार की दीमक इतनी हावि हो गयी है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के संगठन से बड़ा होकर देश की जनता के सामने है। कांग्रेस शासन पर राज्यों से लेकर केन्द्र तक भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनका इतना प्रचार प्रयास हो चुका है कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार का पर्याय मानी जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व इतना कमजोर और लाचार हो गया है कि भ्रष्टाचार के एक भी आरोपी के खिलाफ संगठन के स्तर पर कभी कोई कारवाई नहीं हो पायी है। सारे आरोपों और आरोपीयों को अदालत के सिर पर छोड़ दिया जाता है और अदालतों से ऐसे मामलों पर दशकों तक फैसले नही आते हैं। लेकिन जब एक सीमा के बाद यह आरोप जन चर्चा का रूप ले लेते हैं तो उसका परिणाम यह चुनाव नतीजे बनते हैं। कांग्रेस जब तक संगठन के स्तर पर अपने भीतर फैले भष्टाचार से लड़ने का फैसला नही लेगी तब तक उसका उभरना संभव नही होगा।

आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार अन्ना आन्दोलन का प्रतिफल है। लेकिन आज पंजाब और गोवा की हार संगठन और दिल्ली सरकार का प्रतिफल है। संगठन के स्तर पर आम आदमी पार्टी अभी तक राज्यों में अपनी ईकाईयां स्थापित नही कर पायी है। क्योंकि विचारधारा के नाम पर आप कुछ सामने नही ला पायी है। स्वराज की जो कार्यशैली परिभाषित की जा रही है वह एक स्वतन्त्र राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक चिन्तन का स्तर नही ले पा रही है। भ्रष्टचार के खिलाफ लड़ना और भ्रष्टाचार के वैचारिक धरातल पर चोट करना दो अलग-अलग विषय हैं। आज भाजपा और संघ का विकल्प होने के लिये उसी के बराबर विचारधारा को बहस में लाना होगा और इस बहस के लिये एक स्वस्थ विचारधारा तैयार करनी होगी। क्योंकि यह देश वाम विचारधारा को आज तक स्वीकार नही कर पाया है। बल्कि यह कहना ज्यादा प्रसांगिक होगा कि यदि वामपंथी विचारधारा चर्चा के लिये उपलब्ध न होगी तो शायद दक्षिण पंथी विचारधारा आज सता के इस मुकाम तक न पहुंच पाती।

मनरेगा–लाखों लोगों की जीवनरेखा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक एक लंबा सफर तय कर लिया है और यह लाखों लोगों के लिए एक जीवनरेखा बन गया है। इस अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा सके, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल दस्ती काम कर सकते थे। सामाजिक समावेश, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत विकास महात्मा गांधी नरेगा के संस्थापक स्तंभ हैं। 'शंभू नाथ चौधरी'

वित्त वर्ष 2015 – 16 के दौरान, 235 करोड़ व्यक्ति – दिवस पैदा किए गए, जोकि पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा था। वित्त वर्ष 2016 – 17 के दौरान 4.8 करोड़ परिवारों को 142.64 लाख कार्य – क्षेत्रों में रोजगार दिए गए। इस प्रक्रिया में रोजगार के 200 करोड़ व्यक्ति – दिवस

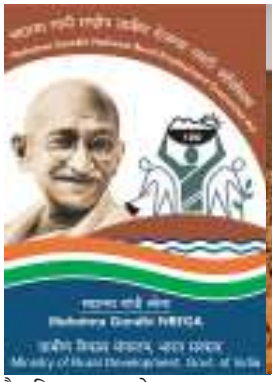

पैदा किए गए। कुल रोजगार का 56 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए पैदा किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक महिलाओं की यह भागीदारी सबसे ज्यादा है।

इस कार्यक्रम के लिए अब तक 3,76,546 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वित्त वर्ष 2017 – 18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जोकि मनरेगा के लिए अभी तक आवंटित राशियों में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 – 17 में 51,902 करोड़ रुपए खर्च किए गए जोकि इसकी शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक खर्च है।

औसतन हर साल (वित्त वर्ष 2013 – 14 तक) 25 से 30 लाख कार्य पूरे किए गए थे, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2016 – 17 में 51.3 लाख काम पूरे किए गए।

इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद पहली बार, जल संरक्षण के लिए समेकित दिशा – निर्देश तैयार किए गए। मिशन जल संरक्षण – प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आईडब्ल्यूएमपी) के साथ मिलकर मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) संबंधित कार्यों के लिए योजना और निगरानी फेमवर्क तैयार किया गया है और इनके लिए वैज्ञानिक नियोजन और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल प्रबंधन का निष्पादन ही मंत्रालय का मुख्य ध्येय है।

वित्त वर्ष 2016 – 17 में कुल खर्च का 63 प्रतिशत हिस्सा एनआरएम (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) कार्यों पर खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2016 – 17 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के कार्यों पर लगभग 70 प्रतिशत खर्च किया गया, जोकि वित्त वर्ष 2013 – 14 में सिर्फ लगभग 48 प्रतिशत था।

भू – मनरेगा तो एक पथप्रदर्शक पहल है, जो बेहतर नियोजन, प्रभावी निगरानी, बढ़ी हुई दृष्यता और अधिक पारदर्शिता के लिए मनरेगा के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों को भू – टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इस पहल की शुरुआत वित्त वर्ष 2016 – 17 में की गई, और लगभग 65 लाख संपत्तियों को भू – टैग किया गया और इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया।

निधि प्रवाह तंत्र के बेरोकटोक चलने और मजदूरी के भुगतान में देरी को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) लागू किया है। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) के द्वारा एमजीएनआरईजीए के कर्मचारियों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013 – 14 में मजदूरी का सिर्फ 37 प्रतिशत भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया था।

अभी 8.9 करोड़ सक्रिय मजदूरों के एनआरईजीए सोफ्ट – एमआईएस में आधार संख्या दर्ज है, जबकि जनवरी 2014 में यह संख्या मात्र 76 लाख थी। अब तक 4.25 करोड़ मजदूरों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के लिए सक्षम किया गया है।

वित्त वर्ष 2016 – 17 के दौरान जॉब कार्ड सत्यापन और अद्यतन प्रक्रिया शुरू की गई थी, और अभियान के रूप में चलाकर 75 प्रतिशत सक्रिय जॉब कार्डों का सत्यापन किया गया और उन्हें अद्यतन किया गया।

वर्ष 2016 – 17 के लिए पहले जारी किए गए 1039 परिपत्रों/परामर्शों और वार्षिक मास्टर परिपत्र (एएमसी) जारी करके मनरेगा को सरल बनाने के लिए पहल की गई। वित्त वर्ष 2017 – 18 के लिए एएमसी जारी किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्टरों की संख्या में कमी करने के लिए औसतन 22 रजिस्टरों की तुलना में 7 सरल रजिस्टरों की प्रक्रिया लागू की गई है। अब तक, 2.05 लाख ग्राम पंचायतों ने इसे अपना लिया है।

यह कार्यक्रम सामाजिक ऑडिट और आंतरिक लेखा परीक्षा की एक अधिक स्वतंत्र और सशक्त प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि महिला एसएचजी से लिए गए सामाजिक लेखा परीक्षकों के एक प्रशिक्षित सामुदायिक काडरों के द्वारा जवाबदेही के साथ – साथ विकास भी सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय ने मनरेगा के मजदूरों का कौशल विकास करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों (Bare Foot Technicians) और प्रोजेक्ट लाइफ (पूर्ण रोजगार में आजीविका) जैसी पहलों को लागू किया है।

मंत्रालय ने अंतरराज्यीय आदान – प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे विचारों और पद्धतियों को साझा किया जा सके। 2016 – 17 के दौरान अब तक, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने इस पहल को लागू किया है और इसमें भागीदारी की।

पहली बार, बुनियादी स्तर पर पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के आधार पर गैर – पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। इन संपत्तियों के भविष्य में पीएमजीएसवाई मानकों के स्तर तक की गुणवत्ता की संभावना होगी।

वर्ष 2015 – 16 के दौरान पहली बार मनरेगा की कार्य – प्रगति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और वर्ष 2016 – 17 के लिए भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। पसूका

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरूणाचल के मुख्यमन्त्री थे। उन्होने अरूणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया औरे इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

गंताक से आगे.....

ताकि इस कानून की मदद से न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जल्द से जल्द इस तरह के कानून को बनाया जाना चाहिए। जिससे देश और जनता के हित में न्याय हो सके।

आज देश में वकील और जज भी भ्रष्ट है। जज का काम संविधान का सही गलत बताना है न कि उसे झूठ बता कर पेश करना और न झूठा फैसला करना। सच कड़वा होता है लेकिन सच मुझे इस हालत में मिलेगा मुझे नही पता था। इस सच का सामना कर मेरी रूह अन्दर तक कांप गयी है। मेरा न्याय से भरोसा उठ गया है। इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहां की भोली जनता का क्या होगा? दोस्तो मैने जो भी बाते यहां बताई है वह शत-प्रतिशत सही है। मैने यह बाते अपने अतंरात्मा से कही है। मैने इन्हें कहीं भी बढ़ा-चढ़ाकर, मिर्च-मसाला मिलाकर पेश नहीं किया है और न ही तथ्यों से कोई छेड़छाड की है।

आज जो बाते हम फिल्मों में देखते और कहानियों पढ़ते-सुनते आ रहे हैं उन्हें हम हकीकत में देख रहें हैं। जिससे यह बात सिद्ध हो गयी की पैसा बोलता हैं। जहां कही भी घटना होती है। वह एक बार ही होती है। जैसे-जैसे Complain, Enquiry, court case, Hearing होती है वैसे स्थति और हालत नहीं बदलते फिर जजों के मत और फैसले क्यों बदलते है? इस देश संविधान के कानून की एक किताब है जो Lower Court, Session Court, High Court और supreme Court में रखी है और उसके बाहर भी देश-दुनिया में उपलब्ध है। जिसे वकीलों और जजों के अलावा और भी लोग पढ़ते है समझते है।

जब कानून की किताब नहीं बदलती तो जजों के फैसले कैसे बदल जाते है? Case मे हार-जीत का फैसला बार-बार क्यों बदलता है किसी भी case में बदलता हुआ फैसला हमें यह बताता है कि कानून के जज बिके हुए है। लेकिन इन फैसलों से सच नहीं बदलता है सच तो अटल और अजर - अमर है जिसे भगवान भी नकार नहीं सकते है।

मैंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में बचपन से ही गांव का प्यार और विश्वास जीता है छात्र समय से ही सभी चुनाव जीते है और आज अपने राजनीतिक जीवन में भी मैने कभी हार का चेहरा नहीं देखा। 1995 में अपने पहले विधानसभा चुनाव से ही मै मंत्री बनाया गया। हर पद पर काम करते हुए मैने बिना बदनामी के कठिनता और मेहनत से कार्य किया हैं जिससे मैने अपनी छोटी सी जिंदगी में समाज, समुदाय क्षेत्र और राज्य के विकास में और लोगों के सेवा में बहुत सा योगदान दिया है। इसलिये मुझे अपने जिन्दगी से कर्मो से कोई गिला-शिकवा पछतावा कोई दुख कोई गम नहीं है। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के दिये गये फैसले को मै अपनी हार नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मै अगर कोई Clarification, Review Petition या SLP दायर करू तो मैं पक्का जीतूंगा। जहां जजों का फिर से कम से कम 80-90 करोड़ रूपये कमाई होगी वह दोनों तरफ से इसलिये मै ऐसा नहीं करना चाहता हूं।

मेरा संदेश

इस राज्य और देश की नादान व भोली जनता को मेरा संदेश सरल और साफ है।

जनता- मै मेरी प्यारी जनता को अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि हमेशा राज्य और समाज हित में ही अमूल्य वोट दे। कभी किसी के दबाव में अपने आने वाले कल को मत मारे और न ही किसी बाहुबली को अपने ऊपर हावी होने दे। चुनावी समय में बांटे गये शराब और पैसो के लिए अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी को दलदल में न धकेले और न ही अपने हक के लिए किसी से कोई समझौता करे। अपना वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख ले और उनके भविष्य के बारे में सोच ले। मैं पक्का दावा करता हूं कि आपका वोट सही उम्मीदवार को ही जायेगा। जनता को उम्मीदवारों के खोखले और चुनावी जुलमों को पहचानना चाहिए। वोट मांगने पर उनसे सच-गलत पर सवाल करना चाहिए और जहां तक हो सके उनकी बीती जिन्दगी उनके आचार-विचार और उनके रवैये को देखकर ही वोट देना चाहिए।

मैने काफी बार यह देखा है कि समाज के बहुत से ईमानदार लोग वोट देने से कतराते हैं वह सोचते है कि उनके एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यह सोच गलत है। जनता का एक- एक वोट हीरे जितना कीमती और बहुमूल्य होता है। क्योंकि उस वोट में लोकतंत्र की वह ताकत होती है जो हर बाहुबली और तानाशाह को उखाड़ फैकने में सक्षम होती है।

जनता यह तय करे और उनका यह फर्ज है कि वह सोच-समझकर अपने हित मे आने वाले उम्मीदवार को ही वोट देकर विजयी बनायें फिर चाहे वह किसी भी कोम, मजहब या समाज का हो। जनता को एक पढ़े-लिखे, संस्कारी, उच्च विचारों से ओत-प्रोत, राष्ट्रीय चिंतन, अपने जीवन में कड़े संघर्ष किया हो। अपने जीवन में दुख देखा व सहा हो और देशभक्त उम्मीदवार को चुनना चाहिए। जिससे समाज के हर वर्ग का फायदा हो सके और राज्य व देश सही दिशा में आगे बढ़ सके।

विद्यार्थी- विद्यार्थीयों को मेरा संदेश इतना है कि वह अपनी पढ़ाई को ही मेहनत और ईमानदरी के साथ करे। आप अपनी पढ़ाई को ही पूजा समझे और पूरी श्रद्धा व शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करे। आप विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान और समझ हासिल करते है वही ज्ञान व विवके आपके जीवन भर साथ रहता है। आपकी हर वक्त ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना और ज्ञान मे ही डूबे रहने की कोशिश होनी चाहिए।

इस समय आप मिट्टी के एक कच्चे घड़े तरह होते है जिसे कैसे भी घुमाकर आकार दिया जा सकता है। लेकिन अगर पकने पर आकार दिया गया तो घड़ा फूट सकता है। इसलिए इस वक्त को पहचान कर आप अपने जीवन को महान बना सकते है। अगर हम किसी भी महान इन्सान की जिन्दगी में झांके तो हम पाएगे कि वह अपने विद्यार्थी जीवन मे ही सबसे ज्यादा संघर्ष कर आगे बढ़ा है। आज आपको सिर्फ अपने Career और लक्ष्य के बारे मे ही सोचना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी चाहिए।

यहां आपको राजनीति और व्यापार से दूर रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते है तो आपका दिमाग पढ़ाई से हट सकता है और आप शिक्षा में पिछड़ सकते है।

हमारे देश में काफी पहले से विद्याश्रम की परंपरा चली हुई हैं जिसमें छात्र अपना घर-परिवार, ऐशों आराम छोडकर आश्रम में पढ़ने जाता था। जहां वह शास्त्र, शस्त्र और राजनीति की शिक्षा लेते थे। आज हमें भी कुछ ऐसी ही शिक्षा निति की जरूरत है जहां हम अपने बच्चों को उनके हिसाब से खेल, संगीत शास्त्र, विज्ञान, गणित और राजनीति की समझ दे सके और उनके सुन्हेरे भविष्य की मंगल कामना कर सके। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने इस कीमती समय और जीवन को एक दिशा व लक्ष्य देकर एक महान पीढ़ी बनाने में अपना योगदान दे। अपने इस समय में राजनीति में न आये और न ही इसके बुरी चालों में फसे। ऐसा कर आप अपने Career को बर्बाद कर सकते है।

मेरा यह मानना है कि छात्र एक NonPolotical Pressure Grop हैं जिसका काम हमेशा सरकार, नेता और अधिकारियों पर ध्यान व निगरानी रखना है और उन्हें गलत काम करने से रोकना है और जनता व समाज के हित में आवाज उठाना है। राज्य और सरकार में हो गलत कामों को भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज अगर छात्र संघ नही उठायेंगे तो कौन करेगा? कौन जनता व समाज को सही दिशा देगा? एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर आप किसी भी क्षेत्र या देश में जा सकते है।

NGO- एक NGO चलाने का सही मतलब राष्ट्रीय का चिंतन करना है। लोगों में जागरूकता पैदा करना लोगों के हित में सोचना और देश में सही-गलत पर अपने विचार रखना है। समाज, राज्य और राष्ट्रीय हित में एक सरकार से ज्यादा NGO की भूमिका होती है। NGO को एक सरकार से ज्यादा सेवा भाव रखना चाहिए।

लेकिन मैने राज्य में ज्यादा Ngo को पैसा कमाते, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते और जनहित के पैसों को गबन करते देखा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना काम छोड़ दूसरों के काम में टांग अड़ाते ज्यादा देखा है। सरकार और अधिकारियों की दलाली में यह बुरी तरह से लिप्त है या यूं कहूं कि इनकी अपनी अलग ही लॉबी है। जिससे वह लोगों से पैसे लूटने में लगे रहते है।

यही कारण है कि आज राज्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की जाती और न ही उनकी आवाज को सुना जाता है। अपनी खोई हुई छवि को वापस पाने के लिए आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए और आपका मुख्य उद्देश्य इंसानियत की रक्षा करना, भ्रष्टाचार, गलत नीतिओं, भेदभाव, ऊंच-नीच, सही-गलत बदमाशों, गरीबों व पिछड़ी जाति को सताने और दंडित करने वालों के खिलाफ लड़ना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भलाई की इस राह में आपके कदम कभी नहीं डगमगाए ।

Leaders- मैं नेताओं को समझना नहीं चाहता । लेकिन अपने सिद्धांतो के चलते जो कुछ देखा और अनुभव किया है। उस पर मन में उठ रहें विचारों को जरूर बताना चाहूंगा। नेताओं और मंत्रियों को मेरा यह कहना है कि अगर आप राजनीति में आने की सोचते हैं तो जनता को अपने परिवार की तरह समझे, और उनके दुःख को अपना दुःख समझकर उन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिश करे। कहने का मतलब है कि बिना जनता के प्यार सहयोग और आर्शीवाद के कोई नेता नही बन सकता।

क्योंकि चुनावी माहौल और चुनावी रैलीयों के दौरान उम्मीदवारों से भी ज्यादा उनके कार्यकर्ता और वोट देने वाले मतदाता बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ काम करते हैं। ज्यादा दौड़-धूप करते है, घर परिवार तक बंट जाते है आपस में लड़ते-झगड़ते है। खून- खराबे तक बात पहुंचने पर भी वह उम्मीदवारों का साथ नहीं छोड़ते केवल इसलिए की उनका उम्मीदवार चुनाव मे जीत कर उनके हित के लिए काम करेंगे- अच्छी सड़के, साफ- सुथरा और निरंतर पीने का पानी , बेहतर शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य, युवाओं को नौकरी उनका रहन-सहन, खान-पान अच्छा हो क्षेत्र में Economy बढ़े, समाज में कानून और शांति का माहौल पैदा हो और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

राजनीति में आने का मतलब कमाई करना ही नही है। बल्कि हम लोगों की सेवा के लिए आये है। अगर हमें कमाई करना है। तो हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है। कमाई करने के बहुत से तरीके हैं जैसे- खेती, व्यापार, नौकरी, सरकारी ठेकेदारी, खेल-कूद और नाच-गाना से भी पैसा कमाया जा सकता है। इन सबके बारे में तो हर कोई आम आदमी भी सोच सकता है व कर सकता है।

लेकिन असल राजनीति तो उस सामाजिक धर्म का नाम है जिसमे आप अपना सुख-चैन, धन-दौलत, नींद-आराम और सब कुछ त्यागकर समाज के हर वर्ग हर तबके को अपनाकर जनता की भलाई करनी चाहिए। आज हमें राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। बांटना नहीं चाहिए। लड़ना- लड़ाना भी नहीं चाहिए। बल्कि हमें राष्ट्रीय एकता अंखडता, सद्भावना और संप्रभुता के हित में सुख- शांति बनाये रखनी चाहिए।

लेकिन मैं इस बात से दुखी हूं कि अरूणाचल राज्य में नेता बनने के बाद वह जनता को भूलकर खुद की ही सेवा करने में लग जाते है। नौकरी की कहीं Post निकलने पर वह अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और जाति को ही चुनते है कुछ Post बचने पर वह उन्हे भी दूसरों को देते है वह भी पैसे लेकर। ऐसी नौकरी तो किसी जरूरतमंद,गरीब और हर तरह से पिछड़े हुए लोगों को ही मिलनी चाहिए। अगर यह गरीब इंसान को नौकरी दे भी देते है तो उनसे घूस मांगते है। इतना ही नहीं घूस लेकर वह अधिकारियों का Transfer भी कर देते है। जिससे अच्छे और काबिल लोगों को काम कर अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। किसी के Promotion करने पर भी यह घूस मांगते है।

राज्य में Contract निकलने पर विधायक और मंत्री अपने बीवी, बच्चों के नाम पर contract लेते है किसी और को contract देने पर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते है। ऐसे में अच्छे और नेक Contractor का क्या होगा? वही काम समय पर पूरा नही होगा और न ही काम में कोई गुणवता (Quolity work) होगी।

राज्य में Schemes जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों के पैसा कमाने के मतलब से बनाई जाती है। यह लोग टैंडर पहले ही तय कर पैसों का हिसाब भी तय कर लेते है कि किसको कितना Persent पैसा मिलेगा।

राज्य में Scheme sanction होने पर काम प्रगति नहीं आती, बल्कि मंत्रियों और विधायकों के खजाने में वृद्धि होती है। जिसे वह मिल -जुल कर हजम कर लेते है सरकार और जनता के Project खत्म होने से पहले ही नेताओं की Building बन जाती है।

असल में Scheme sanction होने के बाद contract का काम 1 साल मे पूरा हो जाना चाहिए और project बड़ा होने पर ज्यादा से ज्यादा 2 सालों के अदर काम पूरा हो जाना चाहिए।

लेकिन अरूणाचल में एक project को 8-9 साल तक लम्बा खिंच जाता है ताकि विधायक और मंत्री ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब भर सके। उदाहरण के तौर पर आप राज्य मे a Secretariate building Assembly building और State Hoppital Naharlagun, MLA cottage, Convernton Hall को देख सकते है। इन योजनाओं को चलते हुए आज 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। Secretairate building ने राज्य में चार मुख्यमंत्रियों को देखा है। जिनमें गेंगो, दोरजी खांडू जोर्बम गम्लिन और नबाम तुकी शामिल हैं लेकिन एक भी मुख्यमंत्री इस काम को पूरा कराने में सक्षम नही थे। इन सभी के कार्यकाल में घोटाले हुए। वही योजना के Fund को 3-4 बार बढ़ाया गया। फिर यह काम अब तक पूरा नही हुआ है।

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर मैने जरूरी fund और Ultimatum देकर 4 महीनों में ही Secretarirte building के काम को पूरा करवाया जिससे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर shifting को तैयार है। इतना ही नही बल्कि इसके साथ Assembly building और State Hospital Naharlagun के काम को भी मैने पूरा करवाने के लिए जरूरी फण्ड देकर Ultimatum दिया था। जिसे की अगस्त महीने में shift किया जाना था। मैने अपनी पूरी मेहनत, जोश और हौसले के साथ काम किया था और यही मेरा कर्तव्य था। मैंने इस राज्य में काम करने की एक मिसाल पेश की है और मैं चाहता हूं कि आगे भी project और योजनाओं को ऐसे ही पूरा किया जाये

– क्रमशः –

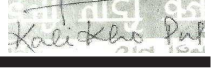

वीरभद्र का भाजपा पर हमला अनुराग ठाकुर पर संगीन इल्जाम

शिमला/शैल। 83 वर्षीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए पार्टी व उसके नेताओं भाजपा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बड़े अनुराग ठाकुर पर संगीन इल्जाम लगाया हैं। ड्रग के धंधें में भाजपा के लोगों के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि

भाजपा नेताओं द्वारा माफिया शब्द पड़ोसी राज्य से उधार लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस प्रदेश में आने वाले ड्रग माफिया के प्रति हमेशा ही सचेत है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा को इस बुराई को रोकने में सहायता करनी चाहिए, परन्तु वे भलीभांति जानते हैं कि उन्हीं की पार्टी के कौन लोग इस अवैध व्यापार में शामिल हैं।

वो यहीं नहीं रुके व कहा कि माफिया शब्द का प्रयोग वहीं कर रहे हैं, जो इन कार्य में संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेता यह भलीभांति जानते हैं कि नशे का व्यापार कहां हो रहा है, तो उन्हें यह बताना चाहिए ताकि इस अवैध व्यापार में लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि ड्रग उत्पाद के नाम पर प्रदेश को बदनाम करना किसी भी हालत में सही नहीं है। इससे लगता है कि भाजपा नेताओं को प्रदेश की कोई परवाह नहीं है और वे अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रदेश को विश्व भर में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के गगरेट में एक विशाल जनसभा में ये सब सरेआम बोल रहे थे। उन्होने कहा कि भाजपा शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने पंजाब को ड्रग माफिया को बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ा।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा माफिया शब्द पड़ोसी राज्य से उधार लिया गया है, परन्तु भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी सहायता नहीं करेगा।

धूमल परिवार व उनके पुत्र अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल के दौरान प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफिया पनपे, जिनमें एक क्रिकेट माफिया के नाम से भी प्रसिद्ध था, जो उनके शासनकाल में फलाफूला। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में भारी संख्या में पेड़ों को काटकार आलीशान फाइव स्टार होटल बनाया गया।

उन्होंने कहा कि कुछ नेता जो लोकसभा के सदस्य बने हैं वे अपने आपको सर्वोपरि समझते हैं। स्वां नदी की 73 छोटी नदियों के तटीकरण का मसला उठाते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं व सांसद अनुराग ठाकुर पर बेहद संगीन इल्जाम लगा दिया व कहा कि प्रदेश भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर एनडीए सरकार को केन्द्रीय हिस्सा न देने के लिए उकसा रहे हैं।

इस मौके पर कांग्रेस एमएलए राकेश कालिया ने भाजपा की मुख्यमंत्री वीरभद्र के खिलाफ झूठे मामले बनाने के लिए भी आलोचना की तथा कहा कि भाजपा हमेशा ही मुख्यमंत्री को बदनाम करने के कार्य में लगी रहती है।

यदि विकास चाहिए तो भगवा लहराना पड़ेगा:धूमल

शिमला/शैल। सौ रैलियों के अभियान की कड़ी में हमीरपुर के गांधी चौक पर 13वीं माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जनसभा को सम्बोधित किया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद अनुराग ठाकुर, संसदीय क्षेत्र के प्रभारी व् प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा, जिला प्रभारी प्रवीण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली में उपस्थित भारी भीड़ खुदबखुद भाजपा और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी व् प्रो. धूमल की दीवानगी का मंजर ब्यान कर रही थी। स्वयं प्रो. धूमल ने अपने सम्बोधन में कहा आज यदि देश में कोई नाम चलता है तो वह है नरेंद्र मोदी और देश में कोई निशान चलता है तो वह है खिलते हुए कमल का निशान। लोगों को समझ आ रही है यदि विकास चाहिए तो भगवा लहराना पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया की आज ही के एतिहासिक दिन 19 वर्ष पहले भाजपा ने 1998 में प्रदेश में सरकार बनाई थी। रैली को जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, रणधीर शर्मा, सांसद अनुराग ठाकुर एवं सतपाल सत्ती ने भी सम्बोधित किया। भाजपा ने हमीरपुर के गाँधी चौक में बड़ी रैली आयोजित कर जहां सन्देश दिया है की हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्त्ता आने वाले चुनावों के लिए तैयार हैं और भोरंज उपचुनाव को बहुमत से जीत दर्ज करवाएंगे।

रैली में पहुँचने से पूर्व बरोह से गाँधी चोंक तक सैंकड़ों युवाओं की बाइक रैली के साथ प्रो. धूमल खुली जीप में शहर वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे। युवाओं के जोश ने माहौल को उत्तसाहित कर दिया था। आज की

रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा और प्रो. धूमल नीतियों पर विशवास जताते हुए भाजपा का विधिवत रूप से दामन थाम लिया। हमीरपुर विस पंचायत प्रतिनिधियों की असोशियेशन के प्रधान ज्योति प्रकाश शर्मा की अगुवाई में दर्जन भर पंचायत प्रधानों ने पूर्व मुख्यमंत्री को मंच पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शुभप्रभात क्लब, युवा मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ एवं वरिस्थ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गुरज देकर और हार पहना कर पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान किया।

शराब के अवैध धंधे में वीरभद्र के रिश्तेदारों का हाथ:सत्ती

शिमला/शैल। हमीरपुर के गाँधी चौक में माफियाराज हटाओ हिमाचल बचाओ रैली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा शराब के अवैध धंधे में जो पंजाबी कल्चर आया है उसमें वीरभद्र सिंह के रिश्तेदारों का हाथ है।

प्रदेश का हर वर्ग आज त्रस्त है क्योंकि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। इसीलिए हिमाचल जैसे सुन्दरता से भरपूर और शांतिप्रिय प्रदेश में माफिया राज हटाओ जैसी रैलियां करनी पड़ रही है। माइनिंग माफियाओं को कोई रोकटोक नहीं है लेकिन रोजगार चलाने वाले ट्रेक्टर वालों का चालान काटा

जाता है। खनन माफिया का राज चला है। दवाई मिले ना मिले लेकिन शराब हर जगह मिल रही है। शराब माफिया का राज चला है। पहले प्रदेश देवभूमि के रूप से जाना जाता था। कांग्रेस का साढ़े चार वर्ष का शासन माफिया राज बनकर रह गया है। क्योंकि प्रदेश का आम व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है। आज प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्ट लोगों का सरगना मुख्यमंत्री बनकर बैठा है तो यह प्रदेश के लोगों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है? जिस वीरभद्र सिंह की इन्फोर्समेंट विभाग और सीबीआई जांच कर रही है दोनों एजैन्सियों के डर से कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मारे मारे फिर रहा है। यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि वीरभद्र सिंह जैसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बन कर बैठा है। इससे ही प्रदेश में माफिया राज की शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जांच एजेंसिया जांच कर रही हों और पार्टी ने उसको ना हटाया हो। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्होंने कहा की भाजपा का प्रदेश में इतिहास नया नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में पार्टी खड़ी हुई है। भाजपा की सरकारें जब जब प्रदेश में बनी हैं तब-तब प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष औद्योगिक पैकेज, सहित अन्गिनत सौगातें मिलीं थी। प्रो. धूमल के समय में सबने पारदर्शी शासन देखा है। पीएमजीएसवाई और नाबार्ड के अंतर्गत प्रदेश की सड़कों के लिए दिए गये विशेष पैकेज उन्ही के शासन काल में मिले। प्रदेश में जब भी भाजपा की सरकार आई तब गाँवों का विकास, शहरों का विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना, आधारभूत ढांचें को मजबूत करना और भाई चारे को बढ़ाना यह भाजपा की सरकारों का काम है चाहे वह प्रदेश में हों या फिर केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनितिक दल जिसमें एक आम कार्यकर्त्ता मेहनत कर आगे बढ़ता हुआ आज देश का प्रधानमन्त्री बना है। किसने सोचा था की क्या एक चाय बेचने वाला प्रधानमन्त्री बन सकता है? भाजपा का कार्यकर्त्ता पोस्टर लगता हुआ आगे बढ़ता है। भाजपा का कार्यकर्त्ता अपने कर्मों से आगे बढ़ता है।

उपायुक्त ऊना ने दिये सरकारी संपति पर लगे पोस्टर, होर्डिंगस हटाने के निर्देश

शिमला/शैल। ऊना, उपायुक्त विकास लाबरू ने कहा कि अधिकारी जिला के विभिन्न हाईवे के किनारे सरकारी संपति, पेडों इत्यादि में अवैध तौर पर लगाए गए पोस्टर, होर्डिंगस, बोर्ड इत्यादि को जल्द हटाया जाए। साथ ही कहा कि जिला के सभी शहरी निकाय अपने-अपने क्षेत्र में विज्ञापन के लिए निर्धारित स्थान को जल्द अधिसूचित करें ताकि इन्ही स्थानों पर विज्ञापन इत्यादि प्रदर्शित किए जा सकें। उन्होने इस सबंध में संबंधित विभागों को आगामी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त यहां प्रशासन में कार्यकुशलता को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

विकास लाबरू ने अवैध तौर पर सरकारी संपति में पोस्टर, होर्डिंगस, बोर्ड इत्यादि लगाने वालों के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को नियमानुसार कडी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मैहतपुर से इंदिरा स्टेडियम ऊना तक मुख्य मार्ग में पार्किंग को बेहतर बनाने, हाईवे के किनारे सभी पैट्रोल पंप में शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होने आगामी ग्रीष्म मौसम को देखते हुए आईपीएच विभाग व खंड विकास अधिकारियों को जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी जल स्त्रोतों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों को अपनी-अपनी पेयजल टंकियों की सफाई करने तथा पेयजल की बर्बादी को रोकने के निर्देश भी दिए। उन्होने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पेयजल की व्यर्थ बर्बादी देखता है तो वह आईपीएच विभाग के टोल फी नम्बर 18001808009 पर कॉल कर सकता है।

डीसी ने कहा कि ऊना जिला में भांग को नष्ट करने के लिए आगामी 15 से 30 जून के दौरान विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गो की समुचित सहभागिता से भांग के पौधों को बडे पैमाने पर नष्ट किया जाएगा। उपायुक्त ने एसडीएम को स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण करने तथा इस बारे प्रतिमाह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। जिला में पोलीथीन के इस्तेमाल को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को चालान करने तथा सब्जी मंडियों में पोलीथीन में सब्जियां लाने व ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

उन्होने बताया कि जिला ऊना में तीन गौसदन कार्यशील हो गए है जिनमें 102 पशुओं को रखने की क्षमता है जबकि नौ अन्य का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि 13 अन्य निर्माणाधीन हैं। उन्होने निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके गौसदनों को क्रियाशील बनाने के लिए जल्द पानी व बिजली का कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों को एलपीजी गैस एजैन्सियों तथा उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस मशीनें लगाने तथा इस बारे लोगों को प्रेरित करने पर बल दिया। साथ ही ई-समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के जल्द निपटारे तथा मुख्य मंत्री की घोषणाओं एवं मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर अमल करने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला ऊना पिछले कई वर्षो से लगातार बेहतर कार्य कर रहा है तथा इस वर्ष भी जिला ऊना प्रदेश में अव्वल रहे इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यो को लेकर विभागों के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भी जल्द जमा करने तथा सरकारी, वन भूमि में अवैध कब्जों को हटाने तथा नए अवैध कब्जों को रोकने के लिए एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होने सभी विभागों को कर्मचारियों की डीपीसी, एसीपी तथा एसीआर को नियमित तौर पर करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी कर्मचारी के लाभ लंबित न रहें।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार मारिया, एएसपी मदन कौशल, एसडीएम पृथी पाल सिंह, सुनील वर्मा, दिले राम धीमान, सहायक आयुक्त विनय मोदी, सीएमओ प्रकाश दडोच सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सोलन में जयकृष्णी पंथ की पद यात्रा का किया स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और यहां के निवासियों की देवी-देवताओं में अटूट श्रद्धा है। मुख्यमंत्री सोलन में जयकृष्णी पंथ की पद यात्रा का स्वागत करने के उपरान्त उपस्थित संत समूह एवं स्थानीय निवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सभी धर्म हमें मानवता, सहनशक्ति एवं सम्पूर्ण मानव जाति के लिए आदर के मूल्य प्रदान करते हैं। हमें इन मूल्यों को बनाए रखने के नियमित प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक स्थानों को आमजन को प्रोत्साहित करने का केन्द्र बनाया जाना चाहिए ताकि सभी सत्य, प्रेम एवं अहिंसा के मार्ग को अपना सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का जीवन विभिन्न देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ है तथा देवी-देवता प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न समारोहों का अभिन्न अंग है।

उन्होंने महाराष्ट्र से आरम्भ हुई पद यात्रा का स्वागत किया तथा आशा जताई कि यह पदयात्रा सभी को पीड़ित मानवता की सेवा की दिशा में और अधिक प्रेरित करेगी।

जयकृष्णी पंथ के प्रमुख गोपीराज महाराज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा पंथ के उद्देश्यों से उन्हें अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने तदोपरान्त सोलन स्थित जौणाजी मार्ग पर कृष्ण मंदिर चौरिटेबल न्यास की आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने सोलन में 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किए जा रहे मिनी सचिवालय के कार्य का निरीक्षण किया तथा इसे 15 मई, 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किए जा रहे परिधि गृह के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलन जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किए जा रहे शामती बाईपास की वस्तुस्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शामती बाईपास के निर्माण कार्य को समय पर पूरा किया जाए।

वीरभद्र सिंह ने इससे पूर्व कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से शहीदेआजम भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव को उनके 86वें शहीदी दिवस पर शहीद स्मारक चम्बाघाट में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

एसजेवीएनएल ने दिया प्रदेश सरकार को 237.38 करोड़ का लाभांश

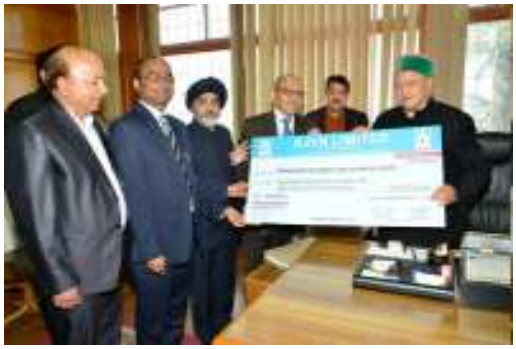

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबन्धक निदेशक

आर.एन.मिश्रा ने 237.38 करोड़ रुपये के लाभांश का चौक भेंट किया। इस अवसर पर मिश्रा के साथ निगम के वित्त निदेशक ए.एस.बिन्द्रा, कार्मिक निदेशक एन.एल. शर्मा व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सार्वजनिक क्षेत्र की एसजेवीएनएल ने वर्ष 2016-17 के वित्तीय प्रदर्शन के तहत 2.25 रुपये प्रति शेयर के तहत हितधारकों को 930.74 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। निगम ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कम्पनी में 25.51 प्रतिशत शेयर के तहत 237.38 करोड़ रुपये का लाभांश प्रदान किया है।

जल विद्युत एसजेवीएनएल की मुख्य शक्ति है और कम्पनी को देश की सबसे बड़ी 1500 मैगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना व 412 मैगावाट की रामपुर में जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन का गौरव प्राप्त है।

हिमाचल ने प्राप्त की क्लोरोपिकरिन रसायन के आयात की स्वीकृति

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से क्लोरोपिकरिन रसायन को मशीनरी व उपकरणों के साथ आयात करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। हिमाचल प्रदेश एचपीएमसी द्वारा शीघ्र ही ट्रिनिटी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी से इसका आयात किया जाएगा ताकि इसे उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन को परीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जा सके।

बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि क्लोरोपिकरिन रसायन का प्रयोग सेब के बागीचों में पुन:रोपण के दौरान गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता व प्रभावशीलता के उपचार के लिए सहायक है, जिससे अन्य फल, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादन को भी बचाया जा सकता है। यह रसायन पॉलीहाउस में फसल चक्र के मध्य मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध होते हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व भर में उपयोग किया जाना वाला क्लोरोपिकरिन स्पैस्फिक एप्पल रेपलेंट डिजीज (एसएआरडी) के खिलाफ लड़ने वाला प्रभावशाली उत्कृष्ट रसायन है। यह रसायन भारत में पंजीकृत नहीं है तथा इसलिए मिट्टी उपचार के लिए इसका आयात या उत्पादन नहीं किया सकता। रसायन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी 1134 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना के अन्तर्गत देश में रसायन के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्लोरोपिकरिन रसायन के आयात की स्वकृति देने के पश्चात अब वर्तमान वर्ष के दौरान शिमला, सोलन तथा कुल्लू जिलों में बहुस्थानीय प्रयोग करवाए जाएंगे। इस निर्णय से भारत में इस रसायन के पंजीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। शिमला, कुल्लू तथा मण्डी जिलों के बागवानों के पुराने तथा जरा-जीर्ण बागीचों में नई किस्मों तथा रूट स्टॉकों को लगाने की जरूरत है तथा यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियानों में से एक है। इस निर्णायक कदम से इन जिलों के बागवानों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे अनेक किसानों द्वारा उठाए गए इस मामले का उचित हल निकलेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि किसानों, विस्तार अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों के लिए यह एक चिंता का विषय है कि नए पौधे एसएआरडी के कारण अच्छी फसल नहीं दे पाते, क्योंकि यह बीमारी तब होती है, जब पौधों को जमीन में वहां लगाया जाता है, जहां समान के समय पहले लगाई गई थी। एसएआरडी न केवल सेब के पेड़ों को प्रभावित करती है, बल्कि गुलाब के पौधों तथा चौरी, नींबू प्रजाति, आडू, नाशपाती तथा पलम तथा श्रीफल जैसे अन्य फलों के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है।

मुख्यमंत्री ने नैनादेवी में अनेक परियोजनाओं के किए लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए।

मुख्यमंत्री ने नैना देवी निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत कुटेहला, तम्बोल और ताली (गातरखाना) के लिए 3.72 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इससे इन पंचायतों के 35 गांवों और 85 बस्तियों की लगभग 12 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

उन्होंने कुटेहला, तम्बोल और जगातखाना पेयजल आपूर्ति योजना के स्तरोन्यन व संवर्द्धन की भी आधारशिला रखी। इस पर 2.68 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी और इससे क्षेत्र के 15 गांव व 35 बस्तियों की 4000 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मुख्यमंत्री ने स्वारघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ट्रामा केन्द्र का भी लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 80 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने स्वारघाट में उपमडलाधिकरी कार्यालय का भी लोकार्पण किया।

उन्होंने स्वारघाट में 2.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन तथा स्वारघाट के नालियां (डढवाल) में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन के निर्माण की भी आधारशिला रखी।

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों के बेसहारा बच्चों ने पूरी की उच्च माध्यमिक शिक्षा

शिमला/शैल। जिला बाल कल्याण समिति, शिमला शिमला जिले में बच्चों की न्यायपीठ के रूप में कार्य कर रही है व उन बेसहारा बच्चों जिनको सरंक्षण एवं देखभाल की आवश्यकता है, के लिए कार्यरत है। जिला बाल कल्याण समिति ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से जिला में संचालित नौ बाल गृहों में लगभग 350 बालकों और बालिकाओं को आश्रय प्रदान किया हुआ है, जहाँ बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त उन के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बाल गृह, सराहन से अधीक्षक मथुरा दास समिति के समक्ष 14 बालकों व उन से सम्बंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हुए। जिला बाल कल्याण समिति ने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके 14 बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया। ये बच्चे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न दूरवर्ती जिलों जैसे चम्बा, कुल्लू, मंडी व शिमला के दुर्गम इलाकों से सरंक्षण हेतु बाल गृह में आश्रय ले कर रह रहे थे। समिति के सदस्यों सुभाष वर्मा, रूनम कौशिक, शीतल ठाकुर, व सपना बंटा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया।

समिति से बातचीत करने पर बच्चों ने बताया की बाल गृह में उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाता था। यहाँ प्राप्त शिक्षा और अनुशासन भविष्य में उन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन बालकों में से कोई इंजीनयर बनना चाहता है, कोई वकील तो कोई डॉक्टर समिति ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए उनको उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने परिजनों से मिल कर बच्चे अत्यधिक खुश थे।

एचपीबीएल अंग्रेजी शराब सीधे उत्पादकों से खरीदती है

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (एचपीबीएल) द्वारा कुछ फर्मों के माध्यम से शराब की आपूर्ति करवाने सम्बन्धी खबर तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि यह हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड उत्पादकों से सीधे तौर पर देसी शराब तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब खरीदती है और फुटकर विक्रेता को सीधे तौर पर आपूर्ति करती है। शराब की खरीद लाईसेंस डिस्टिलरीज तथा बोटलिंग इकाइयां से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने कहा कोई भी फर्म निगम को शराब की आपूर्ति नहीं कर रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भोरंज उपचुनाव के लिये बजट सत्र की अवधि कम की जायेगी

शिमला/शैल। भोरंज उप -चुनाव में सात अप्रैल को वोट डाले जायेंगे और सात अप्रैल को ही तय समय के मुताबिक बजट सत्र समाप्त होगा। प्रदेश विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं। भोरंज उपचुनाव के बाद ही नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। शिमला नगर निगम के चुनावों को प्रदेश का सांकेतिक माना जाता रहा है क्योंकि प्राय:निगम के चुनाव विधानसभा के चुनावी वर्ष में ही आते रहे हैं लेकिन इस बार चुनावी वर्ष में ही यह उपचुनाव आ गया है। अभी संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में भाजपा की सरकारें बन गयी हैं लेकिन हिमाचल के साथ लगते बड़े राज्य पंजाब में कांग्रेस को भी यूपी जैसी ही सफलता मिली है। ऐसे में जहां भाजपा यूपी और उत्तराखण्ड को अपनी बड़ी चुनावी सफलता के रूप में इस उपचुनाव में प्रचारित-प्रसारित करके भुनाने का प्रयास करेगी वहीं पर कांग्रेस पंजाब की सफलता से इसकी काट करेगी। यह उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश में राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा संकेतक बन जायेगा यह तय है। कांग्रेस और वीरभद्र के लिये यह उपचुनाव ज्यादा राजनीतिक अर्थ रखता है।

कांग्रेस ने इस चुनाव के राजनीतिक अर्थों को समझते हुए ही इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को चुनाव प्रचार के लिये आमन्त्रित किया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2003 के चुनावों के दौरान भी अमरेन्द्र सिंह ने इसी हमीरपुर से धूमल पर हमला बोलते हुये आय से अधिक संपति के आरोप लगाये थे। यह आरोप आज भी कांग्रेस के उप महाधिवक्ता विनय शर्मा की शिकायत के रूप में वीरभद्र की विजिलैन्स के पास जांच के लिये लंबित चल रह हैं। वीरभद्र की विजिलैन्स इन आरोपों पर पंजाब सरकार के सहयोग के लिये बादल शासन के समय से ही पत्र लिखती आ रही है। अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी आ गयी है और उसके मुखिया अमरेन्द्र सिंह वीरभद्र सिंह के निकट रिश्तेदार भी बन गये हैं। विजिलैन्स ने अमरेन्द्र की सरकार आने के बाद भी धूमल के संद्धर्भ में पत्र लिखा है। ऐसे में बहुत संभव है कि अमरेन्द्र इस बार भी हमीरपुर आकर धूमल के खिलाफ कोई बड़ा हमला बोल जाये। इस समय प्रदेश कांग्रेस के अन्दर इसके सहयोगी सदस्य बलवरी वर्मा के भाजपा में जा मिलने से राजनीतिक वातावरण में हलचल शुरू हो गयी है। विद्रोह की अटकलें चर्चा में हैं। ऐसे में इस बन रहे राजनीतिक माहौल को शांत और नियन्त्रण में रखने के लिये कांग्रेस और वीरभद्र के पास इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के अलावा और कोई विकल्प नही है। यदि ऐसा नही हो पाया तो कांग्रेस को विखरने में देर नही लगेगी।

दूसरी ओर भाजपा के पास यूपी और उत्तराखण्ड की अभूतपूर्व जीत का जन वातावरण है। इस जन भावना को हिमाचल में भी जमीन पर उतारने के लिये भाजपा को जमीन पर काम करने की आवश्कता है यह सन्देश देने का प्रयास करना होगा कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भाजपा की इस जीत के बाद हताश और निराश हो चुका है और कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना चाहता है। विधायक बलवीर वर्मा और पूर्व प्रवक्ता दीपक शर्मा का भाजपा में शामिल होना इसी दिशा की रणनीति है लेकिन हिमाचल के संद्धर्भ में इस जीत के बाद यह भी चर्चा छिड़ गयी है कि भाजपा में अगला मुख्यमन्त्री कौन होगा? पूर्व मुख्यमन्त्री प्रम कुमार धूमल के साथ ही केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा का नाम भी बराबर चर्चा में आ गया है। नड्डा के प्रदेश दौरों में भाजपा नेताओं का जो वर्ग उनके साथ ज्यादा खड़ा दिख रहा है वह कभी विरोधीयों के रूप में देखा जाता रहा है। इस तरह भाजपा के अन्दर अभी से ही धड़े बन्दी चर्चित होने लग पड़ी है। कांग्रेस इस धड़ेबन्दी को यह कहकर हवा दे रही हैं कि धूमल अब अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। जबकि भाजपा में धूमल का जनाधार नड्डा से कहीं ज्यादा है। इसी के साथ भाजपा का एक वर्ग धूमल-नड्डा के अतिरिक्त यह भी प्रचारित करने लग पड़ा है कि अगला मुख्यमन्त्री कोई तीसरा ही होगा और इस कड़ी में संघ नेता अजय जम्बाल का नाम भी उछाल दिया गया है। भाजपा की यह उभरती और प्रचारित होती गुटबंदी भाजपा के लिये नुकसान देह हो सकती है। इस प्रचारित होती गुटबंदी को भी विराम देने के लिये इस उपचुनाव में भाजपा को इसे प्रमाणित करना आवश्यक होगा।

इस समय इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों के विद्रोही चुनाव मैदान बने हुए हैं। यह संकेत और स्थिति दोनों पार्टियों के लिये चेतावनी है ऐसे में इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा को इसमें जीत का अन्तर बढ़ाने की चुनौती है क्योंकि यह सीट दो दशकों से अधिक समय से भाजपा के पास चली आ रही है। भाजपा का इस समय प्रदेश की राजनीतिक में कोई विकल्प नही है यह संदेश इस जीत का अन्तर बढ़ाने से ही जायेगा। दूसरी ओर वीरभद्र को सातंवी बार मुख्यमन्त्री बनाने के दावे को पूरा करने के लिये यह उपचुनाव जीतना आवश्यक है। ऐसे में अपने-अपने दावों को पूरा करने के लिये वीरभद्र और धूमल दोनों को इस चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत तौर पर उतरना होगा। लेकिन बजट सत्र के चलते दोनों नेताओं को सत्र छोड़कर प्रचार में जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिये समय देने की गरज से सत्र का समय कम करने का फैसला ले सकते हैं।

क्या वर्मा विधानसभा सदस्यता छोड़ेंगे या भारद्वाज अपनी याचिका वापिस लेंगे

शिमला/जे पी भारद्वाज

चौपाल के निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। वर्मा की ही तर्ज पर अन्य निर्दलीय विधायकों के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलों का बाजार

भी देर सवेर अमल होगा तो निश्चित रूप से शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में इस क्षेत्र के राजनेताओं के लिये सरकार और कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करने का यह एक बड़ा कारण बन जाता है। इस पाला बदल के कथित प्रयासों का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा और पाला बदलने वालों का राजनीतिक भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा इस पर अभी कुछ भी कहना ज्यादा सही नही होगा।

निर्दलीय विधायक को चुनाव जीतने के बाद छ: महीने तक यह हक हासिल रहता है कि वह इस अवधि में किसी भी दल में शामिल हो सकता है। इस अवधि में उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन छ:मास के बाद ऐसा करने पर दलबदल कानून के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसमें यदि वह स्वयं विधायक पद से त्यागपत्र न दे तो स्पीकर उसके खिलाफ करवाई करके उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। दलबदल कानून के इसी प्रावधान के तहत भाजपा ने अपने मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज के माध्यम से निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस का सहयोगी सदस्य बनने पर इनके खिलाफ करवाई करने की याचिका स्पीकर के पास दायर कर रखी है जोकि अभी तक लंबित चली आ रही है। ऐसे में विधायक वर्मा को या तो सदन से स्वयं त्याग पत्र देना पड़ता है या स्पीकर को कारवाई करनी पड़ती है। यदि वर्मा भाजपा की प्राथमिकता का फार्म न भरकर केवल सहयोगी सदस्य ही रहते हैं जैसे वह कांग्रेस के साथ थे तो उस स्थिति में भाजपा के लिये एक नैतिक संकट और विधानसभा अध्यक्ष में लिये वैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो जायेगी।

इस परिप्रेक्ष में एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस समय भाजपा ऐसी राजनीतिक गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहन दे रही है। क्योंकि यदि सारे निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणा कर देते हैं तो भी वीरभद्र सरकार पर संकट नही आता है क्योंकि उसके पास अपना बहुमत रहता है। कांग्रेस में यदि दो तिहाई विधायक पार्टी से टूटकर अपना अलग दल बना लेते हैं तभी उन पर दलबदल कानून लागू नही होगा अन्यथा दो चार के छोड़ने से भाजपा को कोई बड़ा लाभ नही मिलता और छोड़ने वालों पर कारवाई हो जायेगी। ऐसे में क्या भाजपा कोई बड़ा खेल खेलने का प्रयास कर रही है। क्या कांग्रेस के अन्दर इस समय वीरभद्र के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह प्रायोजित होने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अन्दर जिस तरह से कुछ नेताओं ने अभी से अगले मुख्यमन्त्री की दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है उससे भी इस तरह के ही

संकेत उभर रहे हैं। कांग्रेस के विद्रोही एक लम्बे अरसे से नेतृत्व परिवर्तन के लिये अपरोक्ष में प्रयास करते रहे हैं। बल्कि इस दिशा में पिछले दिनों चण्डीगढ़ और फिर दिल्ली में भी बैठकें हो चुकी हैं। यह बैठकें निगरान ऐजैन्सीयों की भी निगाहों में रही हैं। जब यह बैठकें हुई थी उस दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं मानी जा रही थी और इन संभावनों के मुद्देनजर प्रदेश के कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं की आप के नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत भी हो गयी थी। यदि पंजाब में वास्तव में ही आम आदमी पार्टी आ जाती तो अब तक प्रदेश में काफी कुछ घट गया होता। इस परिदृश्य में आज यदि भाजपा एक निर्दलीय विधायक को अपने साथ ला रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वह किसी बड़ी योजना को अजांम देने जा रही है।

कांग्रेस व भाजपा के विदेशी चंदा मामले में मोदी सरकार को नोटिस

शिमला/शैल।

देश की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के विदेशी फंड लेने में एफसीआरए के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोई कारवाई न करने पर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को शोकॉज नोटिस जारी किया है कि क्यों ने सरकार के खिलाफ अवमानना की कारवाई की जाए। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के गृह सचिव से चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने दिए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म और पूर्व विदेश सचिव डा. इएएस सरमा ने इस मसले पर मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रणव सचदेवा ने दलील दी कि अदालत ने 28 मार्च 2014 के अपने आदेश में कांग्रेस व भाजपा को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। अदालत ने केंद्र सरकार को दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कारवाई अमल में लाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने कोई कारवाई नहीं की।

यही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए कांग्रेस व भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इन दोनों पार्टियों ने एसएलपी वापस ले ली थी व सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2016 को ये एसएलपी खारिज कर दी थी। अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दायर किया था।

कब से होगी धर्मशाला .....पृष्ठ 1 का शेष

व्यवहार में ऐसा नही है। यदि आज धर्मशाला में कार्यरत कर्मचारी सरकार से शिमला की तर्ज पर राजधानी भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग करे तो क्या उनको यह दी जायेंगी ? स्वाभाविक है कि अधिसूचना में इसके प्रभावी होने के समय का कोई उल्लेख न रहने से कर्मचारियों को ऐसे लाभ से इन्कार किया जा सकता है। कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी यह अधिसूचना कभी भी वापिस ली जा सकती है। क्योंकि यदि इस अस्पष्ट अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो राजधानी के साथ जुड़े वित्तिय और प्रशासनिक प्रावधानों का प्रारूप में कोई स्पष्ट उल्लेख न रहने से इसका कानून की राय में टिका रहना कठिन हो जायेगा।

जीडीपी का 33.96% .....पृष्ठ 1 का शेष

करोड़ ही रखा गया है। इसका सीधा प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ेगा। सरकार के कुल खर्च का आधा भाग केवल कर्मचारियों की पैन्शन और वेतनपर खर्च होगा। वर्ष 2021-22 के कुल 42252.58 करोड़ के खर्च में 21251. 17 करोड़ अकेले इसी मद पर खर्च होगा। सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के स्त्रोतों पर विचार करने की बजाये हर क्षेत्र में आऊट सोर्सिंग के विकल्प पर जाती जा रही है जो कालान्तर में घातक सिद्ध होगा क्योंकि आज ही आऊट सोर्स कर्मीयों के लिये नीति लाने का दबाव सरकार पर आ गया है और इस आश्य की घोषणा भी कर दी गयी है। इसी के साथ बेरोजगारी भत्ता और धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के फैसलों को अमली जामा पहनाने की बात आती है तो बहुत जल्द सरकार की वित्तिय स्थिति खराब हो जायेगी।